web: www.nyaysakshi.com ‖ पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल ‖ पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, सोमवार 26 अप्रैल 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 205

महत्वपूर्ण एवं खास

99 दिन में ही देश में 14 करोड़ 9 लाख से अधिक टीके लगाए गए

नईदिल्ली (आरएनएस)। विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत भारत में कोविड-19 टीके की दी जा चुकी खुराक की कुल संख्या आज 14 करोड़ से अधिक हो गई है। रविवार सुबह सात बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 20,19,263 सत्रों के जरिए कोविड वैक्सीन की कुल 14,09,16,417 खुराक दी जा चुकी हैं। टीकाकरण लाभार्थियों की कुल संख्या में वे 92,90,528 एचसीडब्ल्यू शामिल हैं, जिन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक ली है और 59,95,634 ऐसे एचसीडब्ल्यू भी शामिल हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक ले ली है। इसके अलावा पहली खुराक लेने वाले 1,19,50,251 एफएलडब्ल्यू, दूसरी खुराक लेने वाले 62,90,491 एफएलडब्ल्यू, इसके साथ-साथ 60 साल से अधिक आयु के पहली खुराक लेने वाले 4,96,55,753 और दूसरी खुराक लेने वाले 77,19,730 लाभार्थियों के साथ-साथ 4,76,83,792 पहली खुराक लेने वाले और 23,30,238 दूसरी खुराक लेने वाले 45 से 60 वर्ष की आयु के लाभार्थी भी शामिल हैं।

भारतीय नौसेना ने द्वीपीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोविड- 19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में सहभागिता करते हुए भारतीय नौ सेना के दक्षिणी कमांड के मुख्यालय कोच्चि से नौसेना के जहाज ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिशन के तहत लक्षद्वीप प्रशासन को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसी के तहत आज 25 अप्रैल को सुबह कोच्चि स्थित आईएनएस शारदा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती को रवाना हुआ। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आईएनएस शारदा द्वारा इसके तहत 35 ऑक्सीजन सिलेंडर, रैपिड एंटीजेन परीक्षण टेस्ट किट (आरएडीटी), पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वीपमेंट्स (पीपीई), मास्क और दूसरी वस्तुओं की आपूर्ति की गई। इन वस्तुओं के भंडारण का कार्य आईएनएस द्वीपरक्षक के कर्मियों द्वारा किया गया। इसी मिशन के तहत जहाज द्वारा मिनिकॉय द्वीप पर ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल आपूर्ति भी की गई।

ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरणों को लाने ले जाने वाले जहाजों के लिए सभी शुल्क हटाए:केंद्र सरकार

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश में ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने कामराजार पोर्ट लिमिटेड सहित सभी प्रमुख बंदरगाहों को मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट द्वारा लगाए जाने वाले सभी शुल्क (पोत संबंधी शुल्क, भंडारण शुल्क आदि) हटाने और निम्नांकित चीजों को ले जाने वाले पोतों को बर्थ अनुक्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। बंदरगाहों के अध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से लॉजिस्टिक ऑपरेशनों की निगरानी करने के लिए कहा गया है ताकि बंदरगाह में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस तरह के जहाजों की बर्थ के लिए बेरोकटोक आवाजाही, ऑक्सीजन से संबंधित माल को तेजी से मंजूरी/प्रलेखन और जल्द निकासी के लिए सीमा शुल्क एवं अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

मन की बात में बोले पीएम... फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है पूरा देश

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले और आत्मविश्वास से भरा हुआ था लेकिन इस तूफान (दूसरी वेव) ने देश को झकझोर दिया है। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं आपसे मन की बात एक ऐसे समय कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई और आशंका हो तो सही सोर्स से ही जानकारी लें। आपके जो फैमली डॉक्टर हो, आस-पास के डॉक्टर हों, आप उनसे फोन से संपर्क करके सलाह लीजिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आएं। मोदी ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना की पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश आत्मविश्वास से भरा हुआ था लेकिन इसकी ताजा लहर के 'तूफान' ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि उन्होंने जल्द ही देश के इस आपदा से बाहर निकलने की उम्मीद जताई। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 76वीं कड़ी को प्रधानमंत्री ने पूरी तरह कोरोना महामारी पर केंद्रित रखा और कहा कि आज सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बीमारी को हराना है और इसके लिए देशवासियों को सकारात्मक भाव बनाए रखना है तथा विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों को कोविड-19 रोधी टीकों को लेकर चल रही अफवाहों से भी आगाह किया और कहा कि केंद्र सरकार पात्र नागरिकों को निःशुल्क टीका देती रहेगी। मोदी ने कहा कि आज आपसे 'मन की बात' ऐसे समय कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुःख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय, छोड़कर चले गए हैं।

महाराष्ट्र में सर्वाधिक मौतें

एक दिन में जिन 2,767 मरीजों की मौत हुई है उनमें से 676 की महाराष्ट्र, 357 की दिल्ली, 222 की उत्तर प्रदेश, 218 की छत्तीसगढ़, 208 की कर्नाटक, 152 की गुजरात, 110 की झारखंड और 104 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई। देश में इस महामारी से अब तक कुल 1,92,311 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 63,928 लोगों की महाराष्ट्र, 14,283 की कर्नाटक, 13,475 की तमिलनाडु, 13,898 की दिल्ली, 10,959 की उत्तर प्रदेश, 10,884 की पश्चिम बंगाल, 8,356 की पंजाब और 7,616 लोगों की मौत आंध्र प्रदेश में हुई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, और कर्नाटक में रोजाना 20 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है और यहां रोजाना 15 हजार से अधिक संक्रमण के केस आ रहे हैं।

12 राज्यों में हालात खराब – मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

इन राज्यों में कुल 74.15 फीसदी केस – देश में संक्रमण के कुल मामलों में से 74.15 फीसदी केस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान से हैं। यही नहीं उपचाराधीन 66.66 फीसदी मरीज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और केरल से हैं।

देश में 38 बिजली संयंत्रों के सामने आया कोयले का संकट

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में 46,720 मेगावॉट की सामूहिक क्षमता के 38 बिजली संयंत्रों के पास गुरुवार (22 अप्रैल) तक सात दिन से भी कम का कोयला भंडार बचा था। यह जानकारी केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए) के कोयले के दैनिक भंडार के आंकड़ों से मिली। सीईए की 22 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 1,66,406 मेगावॉट की सामूहिक क्षमता के 135 बिजली संयंत्रों में से किसी के पास कोयला भंडार की स्थिति गंभीर या अति गंभीर नहीं थी। गौरतलब है कि यदि किसी संयंत्र के पास सात दिन से कम कोयला भंडार शेष रहता है तो यह गंभीर स्थिति मानी जाती है। वहीं, तीन दिन से कम का कोयला भंडार अति गंभीर स्थिति होती है। सीईए रोजाना के आधार पर इन संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति की निगरानी करता है। बिजली क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने कहा कि सीईए द्वारा किसी संयंत्र को कोयला भंडार के मामले में गंभीर या अति गंभीर के रूप में वर्गीकृत करने की वजहें हो सकती हैं, लेकिन तथ्य यह है कि बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी है। ऐसे में आगामी दिनों में पारा चढ़ने के साथ खपत बढ़ने से बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बता दें कि देश में 31 मार्च, 2021 तक कुल स्थापित बिजली क्षमता 377 गीगावॉट की थी। इसमें 200 गीगावॉट कोयला आधारित, 48 मेगावॉट पन बिजली और 93 गीगावॉट अक्षय (सौर या पवन) ऊर्जा क्षमता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सौर या पन बिजली स्रोतों से गर्मियों में उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन कोयला आधारित संयंत्र मुख्य लोड उठाते हैं, जो ग्रिड की स्थिरता और गर्मियों के सीजन की ऊंची मांग को पूरा करने के लिए जरूरी है।

नए प्रधान न्यायाधीश ने कश्मीर में इंटरनेट बहाली समेत कई महत्वपूर्ण फैसले दिए

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति एनवी रमण ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जिनमें से एक जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंध का अंत सुनिश्चित करने से जुड़ा था और एक अन्य निर्णय के तहत उच्चतम न्यायालय पारदर्शिता कानून के दायरे में आ गया। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में जन्मे मृदुभाषी न्यायमूर्ति रमण को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।

उनका कार्यकाल 16 महीने से अधिक समय का होगा। वह अगले साल 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे और उन्हें देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच शीर्ष अदालत में कामकाज में सुगमता रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालनी होगी।

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद इंटरनेट प्रतिबंध से जुड़े अनुराधा भसीन मामले में न्यायमूर्ति रमण द्वारा लिखे गए फैसले की अनेक लोगों ने सराहना की थी और इसे प्रगतिशील निर्णयों में से एक करार दिया था। न्यायमूर्ति रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले साल जनवरी में कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट पर कारोबार करना संविधान के तहत संरक्षित है। पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को प्रतिबंध के आदेशों की तत्काल समीक्षा करने का निर्देश दिया था। उनकी अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की वृहद पीठ को भेजने से पिछले साल मार्च में इनकार कर दिया था।

वह पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने नवंबर 2019 में कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है।

रेलवे ने 64 हजार बिस्तर की सुविधा वाले कोविड देख भाल कोच स्थापित किए

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश मौजूदा समय में जब कोविड की दूसरी लहर के संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में रेल मंत्रालय कोविड देखभाल आइसोलेशन कोचों की तैनाती की अपनी पहल को फिर से शुरू कर रहा है। रेलवे ने पिछले वर्ष कोविड-19 के प्रारंभिक संकट के समय अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा की इस पहल को शुरू किया था। तैयारियों के एक उपाय के रूप में, कोविड देखभाल डिब्बों को हल्के लक्षणों वाले कोविड रोगियों के आइसोलेशन के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इन कोचों को अब उपयुक्तता के साथ मौजूदा गर्मी के मौसम की स्थिति को पूरा करने के लिए कूलर, जूट-मैट से सुसज्जित किया गया है।

इस संबंध में, राज्य सरकारों को आइसोलेशन डिब्बों की उपलब्धता और स्थान के बारे में तौर-तरीकों तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर सलाह दी गई है। 64000 बिस्तरों के साथ लगभग 4000 कोविड देखभाल वाले डिब्बे, देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर तैनात किए गए हैं, जिनमें से कुछ पहले से ही कोविड की पहली लहर में मरीजों की आइसोलेशन की जरूरतों को पूरा कर चुके हैं। दिल्ली में, 50 डिब्बे (800 बिस्तर के साथ) शकूरबस्ती स्टेशन पर तैनात किए गए हैं (4 मरीज वर्तमान में भर्ती हैं) और 25 डिब्बे (400 बिस्तर के साथ) आनंद विहार टर्मिनल पर उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 21 डिब्बे (378 बिस्तर के साथ) तैनात हैं और वर्तमान में इन डिब्बों में 55 रोगियों को भर्ती किया गया है। भोपाल स्टेशन पर, 20 डिब्बे तैनात किए गए हैं। पंजाब में तैनाती के लिए 50 डिब्बे तैयार किए गए हैं और 20 डिब्बे जबलपुर में तैनाती के लिये तैयार किए गए हैं।

राज्य सरकारों की मांग पर, ये आइसोलेशन केंद्र हल्के और मध्यम लक्षणों वाले रोगियों की जरूरतों को पूरा करेंगे (जैसा कि राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इन सुविधाओं के बारे में निर्देशित किया गया है)। रेलवे इन रोगियों को खानपान व्यवस्था प्रदान करने और इन कोचों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी प्रयास कर रही है। राज्य सरकारों के आइसोलेशन डिब्बों के उपयोग बारे में समय-समय पर अद्यतन के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

पीएम केयर्स फंड ने देश में 551 संयंत्र लगाने धन के आवंटन की सैद्धांतिक मंजूरी दी

नईदिल्ली (आरएनएस)। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रधानमंत्री के निर्देश के तहत, पीएम केयर्स फंड ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 समर्पित पीएसए (प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन) चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए धन आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पीएम ने निर्देश दिया है कि इन संयंत्रों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। ये समर्पित संयंत्र विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों पर चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। खरीद प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी।

पीएम केयर्स फंड ने इस साल की शुरुआत में देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त 162 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन (पीएसए) मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए 201.58 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पतालों में कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा बनी रहे।

दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल बोले-37 फीसदी तक पहुंचा पॉजिटिविटी रेट

नईदिल्ली। दिल्ली में कोरोना बेकाबू, 37 फीसदी तक पहुंचा पॉजिटिविटी रेट- केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए बढ़ाया लॉकडाउन

राजधानी में एक हफ्ते के लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार नहीं थम रही है और हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने जरूरी घोषणा करते हुए राजधानी में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि को अगले सोमवार तक के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने 19 अप्रैल को एक हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा की थी जिसको अब बढ़ाकर अगले सोमवार यानी 3 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट लगभग 36-37 फीसदी तक पहुंच गया, हमने दिल्ली में इतनी संक्रमण दर आज तक नहीं देखी। पिछले एक-दो दिन से संक्रमण दर थोड़ी कम हुई है और आज 30 फीसदी के नीचे आई है।

वहीं, ऑक्सीजन के प्रबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन के प्रबंधन के लिए हमने एक पोर्टल बनाया है। उत्पादक से लेकर अस्पताल तक सब को हर दो घंटे में अपनी ऑक्सीजन की स्थिति बतानी होगी।

केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रही हैं। दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें केंद्र सरकार से 480 टन ऑक्सीजन अलॉट हुआ है और कल केंद्र सरकार ने 10 टन ऑक्सीजन और अलॉट किया है। अब दिल्ली को 490 टन ऑक्सीजन आवंटित हुआ है, लेकिन ये पूरा आवंटन भी अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचा है।

छत्तीसगढ़ के चौदह जिलों में स्थापित किया जाएगा पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रधानमंत्री के निर्देश के तहत, पीएम केयर्स फंड ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 समर्पित पीएसए (प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन) चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए धन आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पीएम ने निर्देश दिया है कि इन संयंत्रों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। ये समर्पित संयंत्र विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों पर चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। खरीद प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के चौदह जिलों-बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव में पीएसए (प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन) चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

पीएम केयर्स फंड ने इस साल की शुरुआत में देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त 162 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन (पीएसए) मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए 201.58 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पतालों में कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा बनी रहे। इस तरह से अपने स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा से इन अस्पतालों और जिले की दिन-प्रतिदिन की मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा, तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन के टॉप अप के रूप में काम करेगा। इस तरह की प्रणाली यह सुनिश्चित कर सकेगी कि जिले के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक व्यवधान न उत्पन्न हो सके और कोरोना मरीजों व अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके।